संपादकीय जागरण

मंगलवार, 6 मार्च, 2018 : चैत्र कृष्ण 5 वि. 2074

संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है

एफआइआर पर भूल सुधार

यह अच्छा हुआ कि शोपियां में पथराव कर रही भीड़ से खुद को बचाने के क्रम में गोली चलाने वाले सेना के एक मेजर के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश की एफआइआर दर्ज करने के मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह सूचित किया कि सैन्य अधिकारी का नाम आरोपित की सूची में नहीं है। और भी अच्छा यह होता कि शोपियां के हालात से परिचित राज्य सरकार सैन्य अधिकारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का कदम ही नहीं उठाती। निःसंदेह इस मामले में यह भी अपेक्षित था कि मेजर आदित्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज होने के बाद रक्षा मंत्रालय अपनी सक्रियता दिखाता और राज्य सरकार के फैसले का प्रतिवाद करता। समझना कठिन है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेजर आदित्य के पिता को बेटे के बचाव में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा उससे देश की जनता को तो यही संदेश गया कि जो काम रक्षा मंत्रालय को करना चाहिए था वह किसी अन्य को करना पड़ा। आखिर रक्षा मंत्रालय की ओर से यह सवाल क्यों नहीं खड़ा किया गया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने सेना के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने से पहले केंद्र से मंजूरी लेना जरूरी क्यों नहीं समझा? कम से कम अब तो रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकार को अपनी भूल का अहसास हो ही जाना चाहिए। दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कुछ न हो जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़े।

यह समझा जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने राजनीतिक कारणों से सेना के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का काम किया होगा, लेकिन यह वह तरीका नहीं जिससे राज्य के लोगों को सही संदेश दिया जा सके। बेहतर होगा राज्य सरकार अपने स्तर पर राज्य के लोगों के समक्ष यह स्पष्ट करने में संकोच न करे कि सेना उनकी हिफाजत के लिए है और यदि लोग आतंकियों के समर्थन में हिंसक व्यवहार करेंगे तो उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनना होगा। राज्य सरकार को यह भी समझना होगा कि जिन पत्थरबाजों को वह गुमराह युवा बता करके उनके प्रति नरमी बरतती है वे आतंकियों के मददगार और शांति के शत्रु हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि बेहद विषम हालात में आतंकियों से लोहा ले रही सेना के जवानों पर लोग पगलाई भीड़ की तरह पत्थर बरसाएं। हिंसक भीड़ के प्रति सख्ती न बरतने का मतलब है खुद की जान जोखिम में डालना। क्या राज्य सरकार यह चाहती है कि सेना के जवान जान के जोखिम के बावजूद पत्थरबाजों से कुछ न कहें? अगर राज्य सरकार यह चाहती है कि सेना के हाथों कोई अनहोनी न होने पाए तो फिर उसे आतंकियों के समर्थन में होने वाली पत्थरबाजी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना होगा। आतंकियों के खुले-छिपे समर्थकों को आम नागरिक करार देने वाले आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कठिन बनाने का ही काम कर रहे हैं। इससे बुरी बात और कोई नहीं कि इस काम में राज्य सरकार भी भागीदार बने। यदि आतंकियों की घेरेबंदी पर पत्थरबाज उनके बचाव में निकल आ रहे तो यह राज्य सरकार की नाकामी ही है। ऐसी नाकामी सेना के काम को और मुश्किल ही बना रही है।

थमेगा स्तन कैंसर

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए मुफ्त मैमोग्राफी जांच की व्यवस्था की जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए बाकायदा एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही मुख्य सचिव के सामने इसका प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। मैमोग्राफी मशीन मंडलीय अस्पतालों में लगाई जाएगी। पहले चरण में नौ अस्पतालों का चयन होना है और जल्द जगह उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी तक निजी अस्पतालों में यह जांच करवाने में दो से तीन हजार रुपये तक का खर्च आता है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) के मुताबिक देश में महिलाओं में औसतन 23 फीसद कैंसर स्तन कैंसर होते हैं। कैंसर से होने वाली कुल मौतों में 50 फीसद का कारण स्तन कैंसर है। हर साल स्तन कैंसर के 13-14 लाख मामले सामने आते हैं। जानकारी का अभाव भी इसके प्रसार में अहम भूमिका निभा रहा है। पीड़ित महिलाएं संकोच के कारण किसी को अपनी समस्या के बताने में हिचकती हैं, जिससे उनकी बीमारी बढ़ती चली जाती है।

संकोच के कारण कई बार तो महिला ऐसे समय पर डॉक्टर के पास पहुंचती है जब उसकी जान को खतरा बढ़ चुका होता है

संकोच के कारण कई बार तो महिला ऐसे समय पर डॉक्टर के पास पहुंचती है जब उसकी जान को खतरा बढ़ चुका होता है। यहीं पर एनजीओ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार को भी उन्हें साथ जोड़ना होगा। हालांकि काफी पहले से ही स्तन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है लेकिन, जांच सही तरीके से न होने से बीमारी पकड़ में नहीं आती थी, इसलिए मुफ्त मैमोग्राफी जांच के फैसले से स्तन कैंसर के बढ़ते मामलों को कम किया जा सकेगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या त्रिपुरा में माकपा की करारी हार वामपंथ के अप्रासंगिक होने का संकेत है?

आज का सवाल

क्या उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा मिलकर भाजपा को कड़ी चुनौती दे पाएंगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बस्ते के बढ़ते बोझ की चिंता

जगमोहन सिंह राजपूत

बस्ते के बोझ से संबंधित चर्चा नई नहीं है। लगभग तीस वर्ष पहले राज्यसभा में इस मसले को आरके नारायण ने उठाया था

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को आधा करा देने की घोषणा करके स्कूल जाने वाले बच्चों के जीवन में एक बड़ी सुखद संभावना और हलचल पैदा कर दी है। इस खबर से परिचित हुए अधिकांश बच्चों के चहरे पर चमक सी दिखाई देती है। वे यह पूछते हैं कि क्या यह सच में हो जाएगा? कब तक होगा? कैसे होगा? शिक्षा जगत में भी यह इस समय का सबसे अधिक चर्चित विषय बन गया है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि पहले के अनुभवों के कारण उनकी आशाओं पर आशंकाएं हावी हो जा रही हैं। कारण स्पष्ट है कि सरकारी स्कूलों में लगभग उस हर पक्ष में बड़ी कमियां मौजूद हैं जो स्वीकार्य स्तर की शिक्षा पाने और देने के लिए आवश्यक हैं। निजी स्कूल बस्ते का अधिक से अधिक बोझ लादने में आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनमें से अधिकांश सीबीएसई के साथ संबद्ध होने के कारण एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें लागू तो करते हैं, मगर लगभग हर विषय में निजी प्रकाशकों की कम से कम दो-तीन पुस्तकें और भी खरीदते हैं। चूंकि अधिकांश माता-पिता आर्थिक रूप से संपन्न ही होते हैं इसलिए वे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इस बोझ को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें अधिक से अधिक अंक चाहिए, लेकिन बच्चे पर क्या बीतती है इससे वे चिंतित नहीं होते हैं। यही नहीं इस वर्ग के बच्चों को अधिक पुस्तकों के बोझ के साथ-साथ एक से अधिक ट्यूशन और कोचिंग के लिए भी जाना पड़ता है। कुछ उत्साही माता-पिता इसी से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे उन्हें डांस, टेबल-टेनिस, स्विमिंग इत्यादि की कोचिंग में भी भेजते हैं। जाहिर है कि बस्ते के लगातार बढ़ते बोझ के लिए एनसीईआरटी को केवल आंशिक रूप में ही जिम्मेदार माना जा सकता है। निजीकरण, जो एक तरह का व्यापारीकरण ही है, के बढ़ने के साथ बच्चों पर बोझ बढ़ा है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूल हैं जो राज्यों के बोर्ड से संबद्ध हैं। इन स्कूलों में किताबें और स्वेटर भी समय से नहीं मिल पाते हैं। अध्यापक या तो अतिथि अध्यापक श्रेणी के या कम मानदेय वाले ही सारा उत्तरदायित्व निभाते हैं। वे अपने अस्थायित्व से चिंतित और उद्विग्न बने रहने को मजबूर हैं। ऐसे में लगनशीलता और कर्मठता की अपेक्षा का कोई अधिक अर्थ नहीं रहता है। इन स्कूलों में यह प्रश्न सदा ही उभरता है कि इन बच्चों को कौन पढ़ाए, कौन उन्हें प्रोत्साहन दे और समस्या समाधान में सहायक बने? यहां बच्चे पर बोझ और दबाव की प्रकृति बदल जाती है, मगर परिमाण असहनीय ही होता है। व्यवस्था में से कोई भी कमियों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। केवल बच्चा ही फेल घोषित कर दिया जाता है और वह इस अपमान बोध को जीवन भर ढोता रहता है।

बस्ते के बोझ से संबंधित चिंता और चर्चा नई नहीं है। लगभग तीस वर्ष पहले बस्ते के बोझ पर एक देशव्यापी बहस हमारे अत्यंत सम्माननीय साहित्यकार आरके नारायण के राज्यसभा में दिए गए उनके पहले भाषण के बाद प्रारंभ हुई थी। उन्होंने अत्यंत मार्मिक शब्दों में इस चिंताजनक स्थिति का वर्णन किया था जिसे सारे देश ने जाना और उनके प्रयास को सराहा। आरके नारायण ने बताया था कि किस प्रकार बच्चे बस्ते के भारी बोझ के कारण आगे को झुककर चलने को मजबूर होते हैं और इसका उनके स्वास्थ्य पर कितना घातक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बच्चों की पीठ पर प्रतिदिन लादे जाने वाले बोझ के लिए अंग्रेजी का शब्द 'पैक-म्युल' का प्रयोग किया था। आशय था कि हम बच्चों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो खच्चरों के साथ किया जाता है। उनका कहना था कि हम प्रातः बच्चों के ऊपर भारी बस्ते का बोझ लादकर और स्कूल के लिए विदाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। उन्होंने सदन से अनुरोध किया था कि वह इस पर विचार करे और शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार बदले कि बचपन को प्रस्फुटित होने का अवसर मिल सके। सरकार पर असर हुआ और मार्च 1992 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति को बच्चों पर विशेषकर छोटे बच्चों पर बस्ते का बोझ को कम करने के उपाय सुझाने थे और साथ ही साथ सीखने की गुणवत्ता में सुधार और जीवन पर्यंत सीखने के कौशल विकसित करने की भी दिशा देनी थी। इन्हें प्रवेश की अर्हताएं पाठ्यक्रम पूरा होने पर उसके एक-दूसरे से जुड़े पक्षों को भी देखना था। समिति ने गहन विचार-विमर्श और विद्वानों से राय-मशविरा करके अनेक ऐसे महत्वपूर्ण पक्षों का निर्धारण किया जिनमें सुधार आवश्यक थे। इसमें सूचना और ज्ञान के अंतर की समझ पैदा करना अत्यंत जरूरी पाया गया। पाठ्यक्रम बनाने और पाठ्य पुस्तकों के लेखन में ऐसे लोगों की भरमार होना सही नहीं माना गया जो स्कूली शिक्षा से व्यवहारिक रूप से जुड़े नहीं होते हैं। पाठ्यक्रम की केंद्रिकता, उसमें स्थानीय तत्वों की उपस्थिति का अभाव होना और इस कारण उसका अरुचिकर हो जाना भी सामने आया। यह भी पाया गया कि कोठारी आयोग (1964-66) के बाद से अनेकानेक स्तरों पर बार-बार परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए की गई संस्तुतियों का लागू न हो पाना और रटने से बच्चों को निजात न दे पाना भी अनावश्यक बोझ बन रहा है। इस समिति ने 'समझ के बोझ' की भी बात उठाई थी और अध्यापकों और शिक्षण विधि में परिवर्तन के लिए भी संस्तुतियां की थीं। इन सभी पर पुनर्विचार आवश्यक होगा।

यशपाल समिति ने कक्षा छह से दस तक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र को चार विषयों के रूप में न पढ़ाकर एक समेकित विषय सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाने की संस्तुति की थी। समिति की इस सिफारिश पर एक महत्वपूर्ण प्रयास एनसीईआरटी ने सन 2000 में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम की नई रुपरेखा के आधार पर किया। इन चार विषयों में चार पाठ्यपुस्तकों के स्थान पर एक समेकित पाठ्यपुस्तक बनाई गई यानी लगभग 800 पृष्ठों के स्थान पर केवल करीब 200 पृष्ठ, मगर यह प्रयास मई 2004 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद निरस्त कर दिया गया। इसकी संभावना पर फिर से विचार किया जा सकता है। बस्ते के बोझ की समस्या नई नहीं है। इसका समाधान ढूंढ़ने के लिए जिस स्तर के साहस की आवश्यकता थी वह सरकार और मंत्री के स्तर पर पहली बार सामने आया है। जो समाधान सुझाया गया है उसे व्यवहारिक रूप में स्कूलों और कक्षाओं तक पहुंचाने में लिए सघन बहुपक्षीय प्रयासों को निर्धारित कर कर्मठता और लगनशीलता से लागू करना होगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उसके मंत्री ने स्वेच्छा से एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या के समाधान की चुनौती अपने सामने रख ली है उन्हें प्रत्येक राज्य सरकार का सघन और सक्रिय सहयोग अपेक्षित होगा। सबसे पहले सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को आदर्श संस्थान बनाना प्रारंभ किया जा सकता है। चार वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करना सराहनीय कदम है। निजी संस्थानों को रास्ते पर लाना भी आवश्यक होगा। सुप्रशिक्षित अध्यापक-प्रशिक्षक और अध्यापक ही बच्चों के लिए उचित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तथा अन्य गतिविधियों की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। विशेषज्ञ केवल उनकी सहायता कर सकते हैं। देश को शिक्षा सुधार में इन पर विश्वास करना ही होगा।

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

response@jagran.com

कायाकल्प की एक कोशिश

बलबीर पुंज

हजारों करोड़ निवेश के वादे के बाद देखना होगा कि अकर्मण्य और भ्रष्ट नौकरशाही कितनी ईमानदारी से रास्ते पर आएगी?

हाल में उत्तर प्रदेश तीन कारणों से चर्चा में रहा। पहला, लखनऊ में संपन्न हुआ निवेशक सम्मेलन, जिसमें 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश हेतु एक हजार से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दूसरा, प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध योगी सरकार की बढ़ती सक्रियता और तीसरा, राज्य सरकार की नकल विरोधी नीति। भले ही ये तीनों सतह पर अलग-अलग प्रतीत होते हों, किंतु इनका एक दूसरे से गहरा संबंध है। बिना उद्योग-धंधों के किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव नहीं है। यदि वहां गुंडागर्दी और अपराध चरम पर है तो कोई भी उद्योग लगाने और उसे जारी रखने से घबराएगा। परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर सीमित रहेंगे। प्रतिस्पर्द्धा के युग में लचर शिक्षा व्यवस्था के कारण आवश्यक प्रतिभा का अत्यंत अभाव रहेगा जिससे युवा कुंठाग्रस्त होंगे और उन्हे रोजगार ढूंढ़ने में कठिनाई होगी। किसी भी देश-प्रदेश में कानून-व्यवस्था कैसी है, वह मुख्यतः दो स्थितियों से निर्धारित हो सकती है। पहला, क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ है? दूसरा, जनता का पुलिस पर कितना विश्वास है? उत्तर प्रदेश में दशकों से सत्ता-अधिष्ठान के आशीर्वाद से अपराध व्यापार बन गया था। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं की सांठगांठ से संगठित अपराध में शामिल लोग अपने मजहबी जातीय निहित स्वार्थ की पूर्ति करते थे। आज वही समूह वर्तमान सरकार की अपराध के प्रति शून्य सहनशक्ति से इतने हतोत्साहित हो गए हैं कि वह स्वयं को बचाने के जतन कर रहे हैं।

अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई संबंधी कोलाहल के बीच दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल में सैकड़ों लोगों को फर्जी मुठभेड़ों में मार गिराया गया है। सच क्या है? आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 19 मार्च 2017 से लेकर 14 फरवरी 2018 तक उप्र पुलिस ने 40 अपराधियों को मारा गिराया है और 1240 आपराधिक मामलों में कार्रवाई करते हुए करीब तीन हजार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तथाकथित सेकुलरिस्टों के दोहरे मांपदंडों के कारण प्रदेश में अपराध रोकथाम से संबंधित कई महत्वपूर्ण घटनाएं सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा नहीं बन रही हैं। वर्षों से अपनी कार्य संस्कृति और जनता के प्रति आचरण के लिए बदनाम प्रदेश का पुलिस विभाग परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अब पुलिस महानिदेशक थानों में जाकर कनिष्ठ अधिकारियों सहित सिपाहियों के साथ सीधे बैठक कर रहे हैं। हाल के वर्षों में संभवतः पहली बार उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कार्रवाई उनकी जाति, मजहब और राजनीतिक पहुंच देखे बिना हो रही है। पूर्ववर्ती शासन में यहां कानून-व्यवस्था का क्या हाल था, उसका एक शर्मनाक इतिहास है।

शिक्षा विकास का महत्वपूर्ण सोपान है, किंतु उत्तर प्रदेश की गुणहीन शैक्षणिक व्यवस्था ने राज्य की कमजोर नींव को और अधिक खोखला करने का काम किया है। इस संबंध में योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसमें नकल रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना प्रमुख है। इस सख्त नीति का परिणाम यह रहा कि राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे कुल 66 लाख छात्रों में से लगभग 10 लाख परीक्षा से ही भाग गए। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का स्तर भी सोशल मीडिया में वायरल वीडियो से स्पष्ट हो जाता है।

देश-विदेश के कई प्रमुख उद्योगपतियों सहित छह हजार प्रतिनिधियों ने निवेशक सम्मलेन में भाग लेकर भारी निवेश का भरोसा दिया है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने यहां कई घोषाणाएं की हैं। इनमें बुंदेलखंड में 20 हजार करोड़ की लागत वाला रक्षा उत्पाद कॉरिडोर है। रायबरेली कोच फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता में तीन गुणा से अधिक वृद्धि के साथ झांसी में कोच नवीनीकरण फैक्ट्री और फतेहपुर में रेल पार्क की स्थापना है। जेवर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के अतिरिक्त प्रदेश में नौ अन्य एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आइटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। क्या यह सब संभव है? चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद आबादी के संदर्भ में विश्व के पांचवे बड़े देश ब्राजील की कुल जनसंख्या से भी अधिक लोग उत्तर प्रदेश में बसते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 22 करोड़ है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था के समान है, जिसका मूल्य 14.8 लाख करोड़ रूपये है। भारत की कुल जनसंख्या में 17 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के बाद भी उत्तर प्रदेश का देश की आर्थिकी में योगदान लगभग आधा अर्थात 8.24 प्रतिशत है। आर्थिक रुप से पिछड़े उत्तर प्रदेश का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में विशेष स्थान है। शिवभक्तों के लिए काशी, श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा और रामजन्मभूमि अयोध्या इसी भूखंड पर हैं। पौराणिक गाथाओं में उल्लिखित गंगा, यमुना और सरयू जैसी पवित्र नदियां यहीं से होकर बहती हैं। बौद्ध तीर्थस्थल सारनाथ और कुशीनगर भी उप्र का हिस्सा हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। भारतीय पर्यटन का प्रमुख केंद्र ताजमहल भी यहीं है। ऐतिहासिक धरोहरों से सुसज्जित उत्तर प्रदेश उपजाऊ भूमि, प्राकृतिक संपदा, देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति और विशेष भौगोलिकता के मामले में धनवान है। इस राज्य की गणना देश के बीमारु राज्यों में होती है और कई क्षेत्रों की स्थिति तो अत्यंत दयनीय है। वर्ष 1951 के कालखंड में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत दर का 97 प्रतिशत थी जो 2014-15 में घटकर 40 प्रतिशत हो गई है।

समाज का एक वर्ग अक्सर,नोएडा और आसपास के क्षेत्र की संपन्नता को उत्तर प्रदेश के विकास के रुप में प्रस्तुत करता है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि दिल्ली के निकट और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण इस इलाके का विकास संभव हुआ है जिसमें प्रदेश का योगदान सीमित रहा है। क्या उत्तर प्रदेश का समेकित विकसित किए बिना भारत का संपूर्ण उदय संभव है? हजारों करोड़ के निवेश के वादे तो हो गए, किंतु क्या इससे उत्तर प्रदेश का भाग्य बदल जाएगा? यह इस पर निर्भर करता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कायाकल्प हेतु जो लक्ष्य और नीतियां निर्धारित किए हैं उसे लेकर राज्य के अकर्मण्य और भ्रष्टाचार की गोद में बैठे प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी कितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ प्रदेश की विकास यात्रा में शामिल होते हैं? भ्रष्टाचार, अपराध, लचर शिक्षा और प्रशासनिक अकर्मण्यता रूपी जो दुष्चक्र उत्तर प्रदेश के मार्ग में दशकों से कुंडली मारकर बैठे थे उस पर निर्णायक कार्रवाई का समय आ गया है।

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

दुख निवारण

संसार में सभी किसी न किसी कारण दुखी हैं। कोई अधिक, कोई अल्प। दुख स्वाभाविक है जब परिस्थितियां अनुकूल न हों, कभी स्थितियों पर हमारा वश नहीं होता अथवा उनके निदान के हमारे प्रयास विफल हो जाते हैं। वावजूद इसके, हमारे अधिकांश दुखों का कारण हम स्वयं हैं। मन में चल रहे विकार समाज और संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल देते हैं। मन का अहंकार दूसरों की उपलब्धियां देख ईर्ष्या और क्रोध उत्पन्न करता है। मन में बसा लोभ कामनाओं की पूर्ति न होने से क्षोभ और निराशा को जन्म देता है। मनुष्य यह विश्वास कर ले कि वह किसी का भी भाग्यविधाता नहीं है, तो उसके दुख कम हो जाएंगे। यदि वह किसी को कुछ देने की स्थिति में है, तब भी वह दाता नहीं है। दाता एक ही है परमेश्वर। मनुष्य को तो उसने माध्यम बना रखा है। यदि ईश्वर किसी को देना चाहता है तो उसके पास माध्यमों का अभाव नहीं है। उसे देने से रोक लेने की सामर्थ्य भी किसी मनुष्य में नहीं है।

मनुष्य का जन्म माता व पिता के संयोग से हुआ और पंच तत्वों से मिल कर उसका तन बना। इस तन में जीव का निवास परमात्मा की कृपा से ही हुआ। जीव के बिना तन निर्जीव है। तन तभी तक सजीव है जब तक परमात्मा उसमें जीव को स्थित किए हुए है। यह परमात्मा का सबसे बड़ा उपकार है। मनुष्य को तो प्रत्येक सांस हर पल के लिए परमेश्वर का आभारी होना चाहिए कि उसने इतनी सुंदर सृष्टि को देखने का अवसर दिया। परमात्मा की इस महान कृपा के अहसास के साथ जीवन जीने का आनंद ही कुछ और है। जिस परमात्मा ने जीवन दिया है वही इसका संरक्षण भी करेगा। जैसे मनुष्य अपनी बनाई कृतियों से प्यार करता है और उन्हें सुरक्षित रखने के प्रयास करता है, वैसा ही परमात्मा है। परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की और उसे संभाल रहा है। सृष्टि के संचालन का सबसे मुख्य तत्व है संतुलन। जन्म और मृत्य आदि सभी एक निश्चित नियम से आबद्ध हैं। मनुष्य यदि संयम और संतुलन को जीवन का तत्व बनाए तो जीवन सहज और आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। मनुष्य को फल चाहिए, तो जीवन को निरंतर गुणों और शुभ भावनाओं और शुभ कर्मों से सींचता रहे। समय पर उपलब्धियां स्वयं मार्ग में स्वागत करती मिलेंगी। जीवन में दुख कम से कम हों, यह स्वयं पर निर्भर करता है।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

देसी गाय का चमत्कार

पंकज चतुर्वेदी ने अपने लेख 'जमीन पर उतरे गोबरधन योजना' में लिखा है कि कुछ विदेशी किसानों ने भारत की सदियों पुरानी पारंपरिक कृषि प्रणाली को अपनाकर चमत्कारी नतीजे प्राप्त किए हैं। वह शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि अपने ही देश में पश्चिमी उप्र, कानपुर देहात के कुछ हिस्से एवं बिहार के नालंदा जिले के किसानों ने देसी गाय के गोबर-गोमूत्र पर आधारित खेती द्वारा अद्भुत परिणाम प्राप्त कर दिखाए हैं। इस तरह की कृषि लगभग शून्य-बजट की है। लागत नगण्य, परिणाम अकल्पनीय। नालंदा के किसानों ने आलू की कुफ्री पुखराज प्रजाति को प्रति हेक्टेयर 1,088 क्विंटल उपजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके पहले का रिकॉर्ड हॉलैंड के नाम महज 450 क्विंटल का था। वहीं के किसानों ने प्रति हेक्टेयर 224 क्विंटल धान उपजा कर चीन के कृषिशास्त्री युवान लोंगपिंग का 194 क्विंटल का कीर्तिमान ध्वस्त कर डाला है। 660 क्विंटल प्याज प्रति हेक्टेयर पैदा कर हॉलैंड के ही 550 क्विंटल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। इसी प्रकार करेला, लौकी, लहसुन, भिंडी, हरी मिर्च जैसी सब्जियों में वहां के किसान चमक रहे हैं। खेती संबंधी कोई रिकॉर्ड देखना हो, बस नालंदा पर नजर डाल लीजिए तो हॉलैंड-चीन-अमेरिका को भूल जाएंगे। शामली जिले के थाना भवन के एक किसान ने गन्ना उत्पादन नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नोबेल विजेता जोसेफ स्टिगलिट्ज का कहना है कि मात्र 50 प्रतिशत उत्पादन वृद्धि करके कृषि वैज्ञानिक इतराने लगते हैं। भारत में गौ-कृषि द्वारा दोगुनी-तिगुनी उपज देने वाले कृषक पश्चिम के वैज्ञानिकों से कहीं बहुत आगे निकल गए हैं! जरूरत मीडिया द्वारा इसके प्रचार की है।

अजय मित्तल, मेरठ

भाजपा का भय

भाजपा के बढ़ते विजय रथ से घबराकर कर विपक्ष के नेता एकजुट होने लगे हैं। इसकी बानगी यूपी में होने जा रहे उपचुनाव में भी देखने को मिल रही है। यहां एक नए गठबंधन की पहल शुरू हो गई है। बसपा और सपा अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर एक मंच पर आ रही हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई तीसरे मोर्चे की राह तैयार करते दिख रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के सामने एक बड़ा महागठबंधन मुकाबले में हो।

शैलेंद्र सिंह, भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली

अटलजी का कथन

1997 में भाजपा की संसद में बहुत कम सीटें आईं थीं तब कांग्रेसी बहुत उपहास कर रहे थे। इस पर अटलजी ने कहा था कि मेरी बात को गांठ बांध लें। आज हमारे कम सदस्य होने पर आप हंस रहे हैं, लेकिन वो दिन भी आएगा जब पूरे भारत में हमारी सरकार होगी, देश आप पर हंसेगा। पूरब-पश्चिम-उत्तर में भाजपा ने अपना केसरिया रंग फहरा दिया है। आने वाले समय में दक्षिण भारत में भी उम्मीद है कि वहां भी कमल ही खिला दिखेगा। कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है।

mahesh_nenava@yahoo.com

एक साथ चुनाव

भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव सभी विधान सभाओं के साथ शायद इसी वर्ष 2018 में ही कराना चाहती है, यह एक अच्छी बात है। एक साथ चुनाव से निश्चित ही देश को बड़ा लाभ है। यदि ऐसा संभव है तो शायद किसी पार्टी को कभी कोई आपत्ति या एतराज भी नहीं होना चाहिए। यदि ये चुनाव वर्ष 2020 में कराए जाएं तो और भी सही होगा, क्योंकि इससे गिनती भी बैठ रही है।

वेद मामूरपुर ,नरेला

परीक्षा का दबाव

10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके पहले से ही बच्चे काफी तनाव में हैं। वह पढ़ने से ज्यादा ध्यान इन बातों पर लगा रहे हैं कि पेपर कैसा होगा? माता- पिता की अच्छे नंबरों की लालसा के कारण बच्चों में अवसाद बढ़ रहा है। इस संबंध में सरकार सचेत है, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री ने बच्चों से परीक्षा संबंधी बात की है। इसके साथ ही अभिभावकों को भी बच्चों की इस स्थिति को समझना चाहिए। दबाव में बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र होकर पढ़ने दें। इस तरह वह ज्यादा बेहतर कर सकेंगे।

शालू, डा. भीम राव अंबेडकर कॉलेज

विकास की नहीं परवाह

संभवतः भारत के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी को 42 प्रतिशत मत की जीत मिली हो, त्रिपुरा के विधान सभा चुनाव में ऐसा ही चमत्कार हुआ है। भाजपा अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई। भाजपा नीत गठबंधन ने 43 सीट जीत कर 25 साल से सत्ता पर काबिज वाम दलों का मजबूत गढ़ ध्वस्त कर दिया। पहली बार भाजपा व वामदलों में आमने सामने की टक्कर हुई जिसमें भाजपा ने बाजी मार ली। बंगाल में हारने के बावजूद वाम दलों ने अपनी कार्य शैली का आकलन नहीं किया, उन्होंने त्रिपुरा के विकास की कभी परवाह नहीं की। परिणामतः उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। त्रिपुरा में भाजपा की प्रचंड जीत बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस के लिए चेतावनी है।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

ट्वीट-ट्वीट

मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिखी जब भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सरताज सिंह से ही मेडिकल बिल भुगतान के लिए घूस मांगी जा रही है। तब आम इंसान की क्या हालत होती होगी, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया@JM_Scindia

उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होने के नाते मैं राज्य को अपराधियों से मुक्त करने पर पुलिस की प्रशंसा ही कर सकता हूं। जिन तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ताओं का दिल अपराधियों और ठगों के लिए धड़कता है वे कैंडल मार्च निकालने के लिए आजाद हैं। वे कृपया यूपी को बख्श दें।

कंचन गुप्ता@KanchanGupta

एसएससी पर्चा लीक मामले की जांच के आश्वासन पर राजनाथ सिंह जी का आभार। आशा है कि यह जांच महज खानापूर्ति न होकर दोषियों को जेल पहुंचाएगी। युवा अगर सड़क पर है तो संसद को नींद नहीं आनी चाहिए।

कुमार विश्वास@DrKumarVishwas

जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों का कहना है कि अगर आप सही तरह से उर्दू पढ़ें तो मालूम पड़ेगा कि मेजर आदित्य उस इलाके में सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, निजी तौर पर उसमें उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया।

आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

जनपथ

बुआ-भतीजा का हुआ यूपी में गठजोड़,
गेस्ट हाउस वाली सभी याद पुरानी छोड़।
याद पुरानी छोड़ बाढ़ में जब-जब फंसते,
तब-तब मेढक-सांप एक डाली पर दिखते।
सत्ता के हित लोग गधे को कहते जीजा,
उसी भांति ये आज बने हैं बुआ-भतीजा।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 230